V.V. NEWS

वर्ष-13
अंक-30
मूल्य-3
पृष्ठ-4
जौनपुर
25 जुलाई, 2022
सोमवार

सब पर नजर हर खबर पर नजर

वैशवारा

रा. हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/3924/2009
डाक पंजीयन जी आजमगढ़/एन.पी./119/15-16

दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लखनऊ, जौनपुर से एक साथ प्रकाशित

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मियों को दिया कैशलेस इलाज का तोहफा

बोले-सरकार आपकी चिंता करती है, आप जनता की फिक्र करें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को गुरुवार को कैशलेस इलाज का तोहफा दिया है। लोकभवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को कार्ड प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने दस कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को राज्य हेल्थ कार्ड वितरित किए। इस योजना से 22 लाख राज्य कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी और उनके आश्रितों सहित 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

सरकार कर्मचारियों की चिंता करती है वह जनता की फिक्र करें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि हम राज्य कर्मचारियों की पूरी चिंता करते हैं और कर्मियों को चाहिए कि वह जनता की फिक्र करें। हमने कर्मचारियों की वर्षो पुरानी मांग पूरी की है। कोरोना काल में मेरे सामने कर्मियों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव आया था। कुछ राज्यों ने ऐसा किया भी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने न तो कर्मचारियों की संख्या कम की और न ही उनके वेतन आदि में कोई कटौती की। लगातार सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब आप बेफिक्र होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीम वर्क में काम किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी इस अवसर पर आज ही हेल्थ कार्ड दिया जाता तो अच्छा रहता।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड की मांग लंबे समय से थी। आयुष्मान भारत योजना में अन्त्योदय कार्ड धारकों को पांच लाख तक का चिकित्सा बीमा कवर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सरकारी और इम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा के लिए स्टेटहेल्थ कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। यूपी देश का पहला राज्य जिसने कर्मचारियों को यह सुविधा दी। राज्य कर्मचारियों को हम परिवार का अंग मानते हैं। कर्मचारियों को भी चाहिए कि वह जनता के हित के कार्य पूरे मनोयोग से करें। जो भी कर्मचारी कार्य में समस्या बढाते हैं वह तो रिटायर्मेंट के बाद वह खुद समस्या में रहते हैं। अच्छा कार्य करने वालों को लोग रिटायर्मेंट के बाद भी लंबे समय तक याद रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। कोरोना काल में भी कर्मचारियों के हितों को प्रभावित नहीं होने दिया। समय से वेतन –पेंशन दिया गया। हम सब मिलकर राज्य की व्यवस्था को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा ताकि यूपी आने वाले समय में देश का नंबर एक का अर्थव्यवस्था का राज्य बने।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब उपचार कराने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में असीमित मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी और आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के इलाज की प्रति वर्ष मुफ्त सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमे यूनिक नंबर दिया जाएगा।

विश्व में 5 प्रतिशत महिला पायलट, भारत में यह संख्या करीब 15 प्रतिशत:ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली।सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट्स के अनुसार विश्व में कुल पायलटों में से 5 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि भारत में महिला पायलटों की संख्या लगभग 15 प्रतिशत है। लोकसभा में डॉ वी सत्यवती और चिंता अनुराधा के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने देश में महिला पायलटों की संख्या बढाने के लिये उठाये गए कदमों का ब्यौरा मांगा था। सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय और इससे जुड़े संगठनों ने देश में महिला और पुरूषों दोनों वर्ग के पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिये कदम उठाये हैं। इनमें पहले चरण में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पांच हवाई अड्डों.. बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो अैर लीलाबारी पर नौ नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) के लिये अवार्ड पत्र जारी करना शामिल है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में पांच हवाई अड्डों.. भावनगर, हुबली, कउप्पा, किशनगढ़ और सलेम में छह तथा एफटीओ के लिये स्लॉट जारी करना शामिल है। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि इन उपायों से उड़ान प्रशिक्षण संगठनों में उड़ान घंटों और प्रति वर्ष जारी किये जाने वाले वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। सिंधिया ने कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट्स के अनुसार विश्व में कुल पायलटों में से 5 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि भारत में महिला पायलटों की संख्या लगभग 15 प्रतिशत है।

अडानी समूह को 14000 करोड़ रुपये की जरूरत

नई दिल्ली। गौतम अडानी समूह को गुजरात के मुंद्रा में एक नया प्लांट बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए समूह ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से संपर्क किया है। अडानी समूह के प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपये हो सकती है। 15 साल के लिए लोनःमिंट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 15 साल के लोन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एसबीआई लोन के लगभग 5,000 करोड़ रुपये अपने खातों में रखेगा। हालांकि, इस मसले

एसबीआई से मांगा लोन

पर एसबीआई और अडानी समूह की अडानी एंटरप्राइजेज के प्रवक्ताओं को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। मार्च में लिया था लोनःइसी साल मार्च माह में अडानी समूह ने एसबीआई से नवी मुंबई में एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना के लिए 12,770 करोड़ रुपये का लोन भी हासिल किया था। समूह की एक अन्य सहायक कंपनी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह लोन लिया गया था। मुंद्रा में क्या है योजनाःरिपोर्ट के मुताबिक

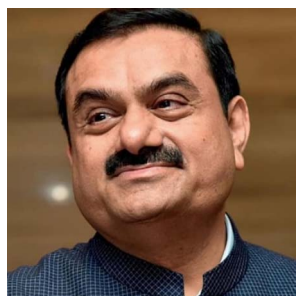

मुंद्रा में कोयले से पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) बनाने के लिए नई सुविधा की योजना बनाई जा रही है। यह प्लांट मुंद्रा में एक पेट्रोकेमिकल क्लस्टर विकसित करने की अडानी समूह की योजना का हिस्सा होने की भी उम्मीद है।

बंगाल की मेगा रैली में ममता बोलीं...

2024 में बीजेपी को नहीं मिलेगा बहुमत, विपक्षी दलों को आना होगा साथ

● सीएम ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का उपयोग अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है। हालांकि, टीएमसी के पास उनसे मुकाबला करने की ताकत है क्योंकि हम उनसे डरते नहीं हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शहीद दिवस रैली में अपने भाषण के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप रखते हुए कहा कि 2024 का चुनाव भाजपा के विभाजन को खारिज करने वाला होगा। ममता ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की बेड़ियों को तोड़ एक जन–समर्थक सरकार स्थापित करें। बारिश का सामना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक कार्यक्रम में हजारों टीएमसी समर्थकों ने भाग लिया। सीएम ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का उपयोग अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है। हालांकि, टीएमसी के पास उनसे मुकाबला करने की ताकत है क्योंकि हम उनसे डरते नहीं हैं। 2024 में, जब भाजपा बहुमत पाने में विफल रहती है, तो विपक्षी दलों को अगली सरकार बनाने के लिए एक साथ आना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और सीपीआई (एम) बारिश को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भगवान भी टीएमसी के साथ हैं। सूरज उज्ज्वल चमक रहा है, ठीक हमारे भविष्य की तरह। जो राज्यों में सरकारें तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें मैं 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे याद कराना चाहती हूं।

पार्टी संगठन को फिर से बनाने निकल पड़े आदित्य ठाकरे...

कहा- शिवसेना का नए सिरे से निर्माण करेंगे

▶ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह नए सिरे से शिवसेना बनाने के लिए निकले हैं। आदित्य ठाकरे ठाणे जिले के भिवंडी शहर में तीन दिवसीय 'शिव संवाद यात्रा' शुरू होने के मौके पर बोल रहे थे। जिले में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

ठाणे।शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पार्टी संगठन को फिर से बनाने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि राज्य में एकनाथ शिंदे नीत सरकार जल्द ही गिर जाएगी क्योंकि यह 'अवैध' तरीके से बनी है। आदित्य ठाकरे ठाणे जिले के भिवंडी शहर में तीन दिवसीय 'शिव संवाद यात्रा' शुरू होने के मौके पर बोल रहे थे। जिले में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदित्य के पिता उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार पिछले महीने गिर गई थी। दरअसल, शिंदे की अगुवाई में पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की एवं भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने रैली में कहा, " एमवीए सरकार ने राज्य में विकास कार्य किए। लेकिन मौजूदा सरकार की कैबिनेट में सिर्फ दो सदस्य (शिंदे और फड़णवीस) हैं। राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है, लेकिन इस स्थिति के बीच में, वे (बागी) हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम ऐसे हथकंडों पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे यकीन है कि यह सरकार गिर जाएगी। यह अवैध तरीके से बनी है।" उन्होंने बागी विधायकों को इस्तीफा देने और फिर से चुनाव का सामना करने की चुनौती दी। आदित्य ठाकरे ने कहा, " शिंदे ने तब विद्रोह किया जब मेरे पिता (उद्धव ठाकरे) बीमार थे।

केंद्र सरकार पर राहुल का निशाना

बोले- जनता की आवाज दबाई जा रही है, तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा

● संसद का सत्र चल रहा है। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर लगातार चर्चा की मांग की जा रही है। इसको लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है। बावजूद इसके चर्चा नहीं हो पा रही है। आज चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अलग–अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर देश की जनता की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि ळैज पर चर्चा करो – सदन स्थगित, महंगाई पर चर्चा करो – सदन स्थगित, अग्निपथ पर चर्चा करो – सदन स्थगित, एजेंसियों के दुरूपयोग पर चर्चा करो – सदन स्थगित। आज सरेआम, देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है। इस अहंकार और तानाशाही पर श्सत्यश भारी पड़ेगा। दरअसल, संसद का सत्र चल रहा है। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर लगातार चर्चा की मांग की जा रही है। इसको लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है। बावजूद इसके चर्चा नहीं हो पा रही है। आज चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके साथ ही आज कांग्रेस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ का मुद्दा भी संसद में उठाया गया। कांग्रेस सांसदों ने इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध किया जिसके बाद सदन स्थगित हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर लगातार निशाना साथ रहे हैं।

गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने किया मुफ्त बिजली का ऐलान

बोले- यह भगवान का प्रसाद है

नई दिल्ली। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार वहां खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इन सबके बीच आज अरविंद केजरीवाल गुजरात के सूरत पहुंचे थे जहां उन्होंने हर परिवार को 300 मिनट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि फ्री में बिजली देना तो भगवान का प्रसाद है। अपने बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 जुलाई से हमने पंजाब में बिजली फ्री की है, लोग चाहते हैं कि गुजरात में भी बिजली फ्री हो जाए। जो हमने दिल्ली और पंजाब में किया है वही गुजरात में करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आप की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात में 300 यूनिट हर परिवार की बिजली फ्री होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं। जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जा रही है उसको भगवान का प्रसाद कहते हैं। फ्री बिजली देना, अच्छे स्कूल बनाना, फ्री में अच्छा इलाज करना ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है।

अब भी देश में 26.9 करोड़ लोग गरीब

नई दिल्ली। याद आ रही है 1956 की वो फिल्म जागते रहो। दरअसल आजादी के बाद जागते रहो शब्द अच्छा लगता था लेकिन अब आजादी के 75वें साल में हम अगर कहे कि जागो सोने वालों! तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रिपोर्ट के जरिये जगाने की कोशिश जरूर होगी। कोई इंसान किस हाल से गुजरता होगा।

जब उसके सामने भूख से तड़पते बच्चे हो और घर में अनाज का एक दाना तक न हो। वैसे तो जब देश आजाद हुआ था उस वक्त करीब 80 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। लेकिन देश के आजादी के अमृत महोत्व यानी 75 सालों में ये घटकर 22 फीसदी से नीचे आकर ठहर गई है। सुनने में ये कानों को सुकून देने वाले आंकड़ें हैं। लेकिन अब एक इसके विस्तार में जाते हुए आपको थोड़ा चौकातें हैं और सुकून से सिकन की ओर भी ले जाते हैं। आजादी के समय 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या 26.9 करोड़ बताई जा रही है। जी हां, सही पढ़ा आपने 26 करोड़ से ज्यादा। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से एक स्टोरी की गई है जिसमें बताया गया है कि ये आंकड़ा लोकसभा में सरकार की ओर से दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से लोकसभा में गरीबी रेखा से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बताया गया है कि देश की 21.9 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। हालांकि ये आंकड़े 2011–12 के बताए जा रहे हैं, क्योंकि आगे के गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या का हिसाब ही नहीं लगाया गया। आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली सबसे ज्यादा आबादी छत्तीसगढ़ की है। झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश और यूपी ऐसे राज्य हैं, जहां 30 फीसदी या उससे ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती है।

क्या है तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट

साल 2011–12 में गरीबों की संख्या का पता लगाने वाला आंकड़ा जारी किया गया था। जिसे आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकसभा में भी सरकार की तरफ से यही आंकड़े दिए गए। जिसे तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर निकाला गया था। इसके मुताबित गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति हर दिन 26 रुपये और शहरी व्यक्ति 32 रुपये खर्च कर रहा है। तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। यानी, गांव में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 816 रुपये और शहरी व्यक्ति एक हजार रूपये खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 25 जुलाई, 2022

सम्पादकीय.....

नये मुकाम पर पीवी सिंधु

सिंगापुर ओपेन ट्रॉफी में पीवी सिंधु की जीत भारतीय बैडमिंटन के इतिहास की शानदार परिघटना है. इस साल यह उनकी तीसरी लगातार जीत है. वे इस माह के अंत में शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. सिंधु की जीत के हवाले से कुछ बातें जेहन में आती हैं. एक तो यह कि ओलिंपिक या वैश्विक स्तर पर जो प्रतिष्ठित खेल हैं, उनमें किसी खेल में अगर भारत बहुत मजबूती से प्रदर्शन कर रहा है, तो वह बैडमिंटन है. इस खेल में साइना नेहवाल से शुरू हुई यात्रा नये मुकाम की ओर जाती दिख रही है. नेहवाल के बाद से ऐसा कोई ओलिंपिक आयोजन नहीं है, जिसमें भारत ने बैडमिंटन में पदक न हासिल किया हो. दो पदक तो सिंधु ही जीत चुकी हैं. नेहवाल ने एक मेडल लंदन ओलिंपिक में जीता था. दूसरी बात यह है कि जो खिलाड़ी पदक पाने में कामयाब नहीं रहे, उनका प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा और वे मुकाबले में अंत तक जमे रहे थे. अगर हम दो साल बाद के ओलिंपिक को देखते हैं, तो सिंधु समेत कई ऐसे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो मेडल के हकदार नजर आते हैं.हाल ही में भारत ने बैडमिंटन का प्रतिष्ठित थॉमस कप जीता है. वह जीत किसी भी खेल के टीम इवेंट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है. कई लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं, पर मेरी राय यही है कि यह 1983 के क्रिकेट विश्व कप से भी बड़ी जीत थी. हम ओलिंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतते रहे थे, उससे भी बड़ी जीत थॉमस कप की इसलिए है कि वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धा वाला खेल है. सौ से अधिक देश गंभीरता से बैडमिंटन खेलते हैं. अगर हम ओलिंपिक हॉकी के इतिहास को देखें, तो उस समय लगभग आधा दर्जन देश ही मुख्य रूप से हावी थे. क्रिकेट को या किसी भी खेल को मैं कमतर नहीं आंकता, पर यह सच है कि एक दर्जन से भी कम देश गंभीर क्रिकेट खेलते हैं. पीवी सिंधु की यात्रा को अगर आप देखें, उनकी तरह व्यक्तिगत खेलों में उपलब्धियां हासिल करने वाला और कोई खिलाड़ी किसी भी खेल में नजर नहीं आता.इसकी वजह यह है कि उनके पास विश्व चौंपियन का खिताब है, ओलिंपिक के मेडल हैं और कई विश्व स्तर की अन्य जीतें हैं. बैडमिंटन में चाहे हम प्रकाश पादुकोण का नाम लें, पी गोपीचंद का नाम लें, साइना नेहवाल का नाम लें, इन सबसे लंबी लकीर पीवी सिंधु ने खींच दी है. हम यह जरूर चाहते हैं कि वे ऑल इंग्लैंड चौंपियनशिप भी जीतें क्योंकि भारत में उसे एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है. इस टूर्नामेंट को छोड़ दें, तो अन्य सभी बड़े आयोजनों में सिंधु ने नाम हासिल किया है.यह सवाल स्वभाविक है कि अब पीवी सिंधु का करियर किस ओर जायेगा. बीते कुछ वर्षों की उनकी यात्रा को देखें, तो यह साफ दिखता है कि उन्होंने यह अच्छी तरह सीख लिया है कि उन्हें कब ऊपर उठना है. तोक्यो ओलिंपिक के समय यह कहा जा रहा था कि सिंधु फॉर्म में नहीं है, लेकिन ठीक ओलिंपिक से पहले उन्होंने अपने को पिक किया और मेडल लेकर आयीं.विश्व चौंपियनशिप के दौरान कहा जा रहा था कि सिंधु सिल्वर मेडल ही क्यों पाती हैं. तब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. ऐसा ही इंडोनेशिया ओपेन और सिंगापुर ओपेन में भी हुआ. इसका सीधा मतलब है कि जो खिलाड़ी अपने को पिक करना जानता है, वह अपने करियर को लंबा करना भी जानता है. इसे देखते हुए लगता है कि आगामी कुछ वर्षों, जिनमें ओलिंपिक भी शामिल है, में पीवी सिंधु कड़ी टक्कर देती रहेंगी. इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है. वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, सो उम्मीदें भी हैं. भारतीय बैडमिंटन (महिला व पुरुष दोनों) में अच्छे खिलाड़ियों का एक समूह उभर कर सामने आया है. लक्ष्य सेन से बहुत अपेक्षाएं हैं. ये खिलाड़ी भारतीय बुलंदी के झंडे को आगे ले जाने में सक्षम हैं. हम भारतीय बैडमिंटन की सक्सेस स्टोरी को पुलेला गोपीचंद की एकेडमी तक ले जाकर रोक देते हैं. लेकिन देश में अनेक ऐसे प्रशिक्षण केंद्र बने हैं, जहां अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और वे प्रकाश पादुकोण, नेहवाल, गोपीचंद, सिंधु जैसे खिलाड़ियों को आदर्श मानकर अपने को बेहतर बना रहे हैं.उनमें भी यह आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि इन खिलाड़ियों की तरह वे भी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में अपना नाम कर सकते हैं. पहले के दौर में यह माना जाता था कि केवल क्रिकेट खिलाड़ी ही आइकन हो सकते हैं, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, एमएस धौनी, विराट कोहली जैसे कई क्रिकेटर युवाओं के आदर्श बने. पर बीते कुछ सालों में परिदृश्य तेजी से बदला है.पीवी सिंधु जैसे आइकन के आने से किशोरों व युवाओं में ओलिंपिक खेलों में भी अच्छा करने की प्रेरणा मिली है. सिंधु की पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यवर्गीय है. उनके माता–पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे. उनकी बहन डॉक्टर हैं. ऐसे परिवार के एक सदस्य को बैडमिंटन से जोड़ना और उस पर पूरा दांव लगाना निश्चित ही उत्साहजनक उदाहरण है. आने वाले समय में हमें अनेक खेलों में ऐसे स्टार देखने को मिल सकते हैं.

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का बिखराव कोई नई बात नहीं

अनिल जैन

राष्ट्रपति पद के 16वें चुनाव के लिए मतदान हो गया है। उसके दो दिन बाद यानी 21 जुलाई को नतीजा घोषित हो जाएगा। भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर किसी को भी संशय नहीं है, क्योंकि उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें भाजपा के घोषित–अघोषित सहयोगी दलों के अलावा कुछ विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। उन्हें समर्थन देने वाले कुछ क्षेत्रीय विपक्षी दल ऐसे भी हैं, जिनका शीर्ष नेतृत्व कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच में फंसा हुए है तो कुछ ने अपनी पार्टी और सरकार को भाजपा के बहुचर्चित श्ऑपरेशन लोटसश से बचाने के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया।द्रौपदी मुर्मू को मिले इसी समर्थन को लेकर इस बात का बहुत शोर मचा कि राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला की उम्मीदवारी से विपक्षी दलों की एकता छिन्न–भिन्न हो गई। सरकार के प्रचार तंत्र की भूमिका निभाने वाले टीवी चौनलों पर इस बात को लेकर लंबे–लंबे कार्यक्रम हुए जिसमें अपढ़–कुपढ़ एंकरों ने बताया कि भाजपा के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष किस तरह धराशायी हो गया। यह सही है कि राष्ट्रपति चुनाव में कुछ विपक्षी दलों ने अलग–अलग कारणों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जिस पर हैरान हुआ जाए। अपवाद स्वरूप कुछेक चुनाव को छोड़ कर राष्ट्रपति के हर निर्वाचन में विपक्ष के वोट बंटते रहे हैं। इन चुनावों में उम्मीदवार की सामाजिक अथवा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर या अन्य कारणों से पार्टियों ने समर्थन या विरोध का फैसला किया है, जैसे कि अभी शिव सेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आदि ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था। सत्ताधारी कांग्रेस ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वे 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही राष्ट्रपति बन गए थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उनका कद काफी ऊंचा था, इसलिए विपक्षी दलों ने भी उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। अलबत्ता चार निर्दलीय उम्मीदवार जरूर उनके खिलाफ मैदान में थे, जिनमें केटी शाह सबसे गंभीर उम्मीदवार थे। समाजवादी विचारधारा के शाह उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा विधिवेत्ता थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट हासिल कर विजयी हुए थे, जबकि केटी शाह को 92,827 वोट मिले थे। राष्ट्रपति पद के लिए 1957 में हुए दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस की ओर से राजेंद्र प्रसाद ही उम्मीदवार थे। उस चुनाव में भी न तो विपक्ष ने कोई उम्मीदवार खड़ा किया और न ही निर्दलीय रूप से कोई गंभीर उम्मीदवार मैदान में उतरा, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद आसानी से जीत गए। 1957 में राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चुनाव भी एकतरफा रहा क्योंकि उनके खिलाफ भी विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। राष्ट्रपति पद के लिए 1967 में हुए चौथे चुनाव में पहली बार कांटे का मुकाबला हुआ। कांग्रेस ने डॉ. जाकिर हुसैन को और उनके खिलाफ विपक्ष ने जस्टिस कोटा सुब्बाराव को अपना उम्मीदवार बनाया। सुब्बाराव सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे थे। राष्ट्रपति पद के लिए यही एकमात्र चुनाव रहा जिसमें समूचा विपक्ष एकजुट रहा। इस चुनाव में डॉ. जाकिर हुसैन को 4,71,244 जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुब्बाराव को 3,63,971 वोट मिले थे। डॉ. जाकिर हुसैन का अपने कार्यकाल के दूसरे ही साल में निधन हो जाने की वजह से 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए पांचवां चुनाव हुआ, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे और उनके खिलाफ तत्कालीन उप राष्ट्रपति वीवी गिरि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे। उस चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन न करते हुए परोक्ष रूप से वीवी गिरि का समर्थन किया और सभी सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने नेहरू काल में वित्त मंत्री रहे चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख को अपना उम्मीदवार बनाया। कुछ विपक्षी और क्षेत्रीय पार्टियों ने वीवी गिरि को तो कुछ ने संजीव रेड्डी को समर्थन दिया। कश्मकश भरे चुनाव में वीवी गिरि को 4,20,077 जबकि संजीव रेड्डी को 4,05,427 और देशमुख को 1,12,769 वोट मिले। 1974 में छठे राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद का चुनाव लगभग एकतरफा रहा। विपक्ष ने उनके खिलाफ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता त्रिदिब चौधरी को मैदान में उतारा, लेकिन वे कहने भर को ही विपक्ष के उम्मीदवार थे। वामपंथी दलों के अलावा किसी विपक्षी पार्टी का उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिला। फखरुद्दीन अली अहमद का निधन भी अपने कार्यकाल के दौरान ही 1977 में हो गया, जिसकी वजह से नए राष्ट्रपति का चुनाव 1977 में ही कराना पड़ा। यह राष्ट्रपति पद के लिए सातवां चुनाव था और केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। पांच दलों के विलय से बनी जनता पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में। जनता पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था। यही एकमात्र ऐसा चुनाव रहा जिसमें राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। 1982 में आठवें राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो चुकी थी। ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे जबकि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देने वाले जस्टिस एचआर खन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में विपक्षी दल कमोबेश एकजुट रहे लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनके कमजोर संख्या बल के चलते जैल सिंह आसानी से जीत गए। 1987 में नौवें रार्ष्ट्रपति का चुनाव भी एकतरफा रहा। कांग्रेस के आर.वेंकटरमण 7,40,148 वोट हासिल कर विजयी रहे, जबकि उनके खिलाफ संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर को 2,81,550 वोट मिले। 1992 दसवें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में डॉ. शंकर दयाल शर्मा सत्तापक्ष के उम्मीदवार थे और संयुक्त विपक्ष ने उनके खिलाफ लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे मेघालय के वरिष्ठ सांसद प्रो. जॉर्ज गिल्बर्ट स्वेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में भी विपक्ष कमोबेश एकजुट ही रहा लेकिन उसके कमजोर संख्याबल के चलते शंकरदयाल शर्मा आसानी से जीत गए। हाल के इतिहास में सबसे एकतरफा चुनाव 1997 में ग्यारहवां राष्ट्रपति चुनाव हाल के इतिहास का सबसे एकतरफा चुनाव रहा। इस चुनाव में सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा ने तत्कालीन उप राष्ट्रपति केआर नारायणन को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्हें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस तथा भाजपा ने भी समर्थन दिया था लेकिन वे निर्विरोध नहीं चुने जा सके, क्योंकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए थे। उन्हें शिव सेना ने समर्थन दिया था। साल 2002 में बारहवें राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस विपक्ष में थी और भाजपा नीत एनडीए की सरकार थी। एनडीए ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कलाम के नाम पर सहमत हो गए थे लेकिन वामपंथी दलों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रहीं कैप्टन लक्ष्मी सहगल को कलाम के मुकाबले अपना उम्मीदवार बनाया था। यह मुकाबला भी एकतरफा था। 2007 में तेरहवें राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनके खिलाफ विपक्ष ने तत्कालीन उप राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को मैदान में उतारा। शिव सेना उस समय भाजपा की प्रमुख सहयोगी थी लेकिन उसने शेखावत के बजाय प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। 2012 में चौदहवें राष्ट्रपति के चुनाव में सत्तापक्ष के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी थे। विपक्ष ने उनके खिलाफ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा को अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन इस बार भी शिव सेना ने बाकी विपक्षी दलों से अलग लाइन लेते हुए मुखर्जी का समर्थन किया। यही नहीं, उस समय एनडीए में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस उम्मीदवार मुखर्जी का समर्थन किया था। 2017 पंद्रहवें राष्ट्रपति समय भाजपा सत्ता में आ चुकी थी और उसने रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था,जबकि विपक्ष की ओर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार मैदान में थीं। उन्हें 17 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था लेकिन जनता दल (यू) ने विपक्षी खेमे में होते हुए भी भाजपा के उम्मीदवार कोविंद का समर्थन किया था। इस प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए सभी चुनावों में से कुछ को छोड़ कर ज्यादातर में विपक्ष कभी एकजुट नहीं रहा। इसलिए इस बार भी विपक्ष अगर बंटा हुआ है तो यह कोई अनहोनी घटना नहीं है और इस पर मीडिया का उछलना व शोर मचाना बेमतलब है।

भारत के लिए अनुकूल है आइ2यू2

प्रो सतीश कुमार

विश्व राजनीति की नियत और प्रकृति एक समान नहीं होती. वह समय और परिस्थिति के अनुरूप करवटें लेती है. पिछले दिनों जो कुछ हुआ, वह भारत की विदेश नीति के पक्ष में हुआ. अमेरिका, भारत, इजरायल और यूएई ने पिछले साल अक्तूबर में एक समूह बनाने की पहल की थी. नौ महीने में यह ढांचा तैयार हो गया और हाल में इस समूह की शिखर बैठक भी संपन्न हो गयी. शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बैठक से आई2यू2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है. हमने कई क्षेत्रों में साझा परियोजनाओं का एक रोडमैप बनाया है. आई2यू2 समूह बनाने की मांग 18 अक्तूबर, 2021 को चार देशों के विदेशमंत्रियों की बैठक में पेश की गयी थी. आई2यू2 से तात्पर्य 'भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई' से है. संगठन का उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे छह अहम पारस्परिक क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना हैपानी की समस्या, ग्रीन एनर्जी की किल्लत, खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त रूप से काम किया जायेगा. भारत में फूड कोर्ट के लिए पहल की गयी है. संगठन के भावी समीकरण को समझने की कोशिश करें, तो कई आयाम दिखायी देते हैं. इसके साथ ही, इस क्षेत्र में विविधता और कूटनीतिक विसंगतियों की चर्चा भी जरूरी है. शीतयुद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया को दो अलग–अलग खेमों में बांट दिया था. इजरायल–फिलीस्तीन टकराव को उसने मोहरा बनाया और पश्चिम एशिया के चंद देशों को अपना पिट्ठू. तेल व्यापार पर पकड़ मजबूत करने के लिए उनके बीच के तालमेल को कभी बढ़ने नहीं दिया. दूसरी तरफ, पाकिस्तान के बहाने अमेरिका भारत को पश्चिम एशिया से दूर ही रखा. भारत की परंपरागत विदेश नीति भी वैचारिक रूप से अलग बनी रही और इजरायल–फिलीस्तान के द्वंद्व में वर्षों तक अटकी रही. भारत 1950 में इजरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है, लेकिन उसके साथ कोई कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करता. दोनों देशों के बीच कोई व्यापारिक तंत्र नहीं बना. इसका एक कारण यह भी था कि भारत का मुस्लिम समाज नाराज हो जायेगा. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए. लेकिन, यह नीति ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुई, या कहें गर्मजोशी का अभाव उसके बाद भी बना रहा. इस दौरान कोई उच्च स्तरीय यात्रा नहीं हुई. न हमारे प्रधानमंत्री वहां गये और न ही न्योता दिया. साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया. विदेशनीति में यह क्रांतिकारी बदलाव था. फिर मनमोहन सिंह ने 10 साल के कार्यकाल में चार बार खाड़ी के देशों की यात्रा की. लेकिन, हर बार यह यात्रा बहुपक्षीय बैठक के सिलसिले में हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया को नये नजरिये से देखना शुरू किया. यूएई के साथ व्यापारिक संबंध के साथ–साथ सामरिक संबंधों की नींव डाली गयी. दूसरी तरफ, इजरायल के साथ भी सैन्य और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया गया. चारों देशों के समूह की नींव इसी बदलाव का नतीजा है. रूस और चीन एक साथ हुए, चीन और अमेरिका के बीच द्वंद्व बढ़ा. ऐसे में पश्चिम एशिया की रणनीति में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनती गयी. यह समूह भारत के लिए कई तरह से मददगार साबित हो सकता है. पहला, खाड़ी के देश आपसी संघर्ष और द्वंद्व में बंटे हुए थे. लेकिन, एक दशक से उनके बीच भी बदलाव आया है. यह बदलाव भारत की सोच के अनुरूप है, इसलिए पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए सहायक होगा. मसलन, एतिहाद रेल प्रोजेक्ट 2030 तक खाड़ी देशों को एक साथ जोड़ देगा. इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा. दूसरा, पाकिस्तान की मुस्लिम केंद्रित कूटनीति भारत के विरोध में कारगर नहीं रही. साल 2019 में कश्मीर से धारा–370 की समाप्ति कर भारत ने जब बुनियादी बदलाव को अंजाम दिया था, तब संयुक्त अरब अमीरात ने इसका समर्थन किया था. ओआईसी यानी इस्लामी सहयोग संगठन, जो मुस्लिम बहुल देशों के बीच में बहुत प्रभावकारी था, वह भी अब कमजोर पड़ चुका है. भारत के साथ खाड़ी के देशों की सोच में बदलाव आ चुका है. तीसरा, भारत पश्चिम एशिया में अपनी ताकत और शक्ति के बूते पर है, न कि अमेरिकी रहमो–करम पर. आज इस क्षेत्र को एक नया स्वरूप देने में भारत की अहम भूमिका है, इसलिए बदलाव भारत की सोच के कारण से भी होगा. ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर ईरान भी इस ग्रुप का अंग बन जाये. इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि रूस भी चारों देशों के इस संगठन में शामिल हो जाये. क्योंकि, रूस का संबंध इजरायल और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे हैं. रूस जिस तरीके से क्वाड को देखता है, उस नजरिये से आई2यू2 को नहीं देखता. चौथा, पश्चिम एशिया और खाड़ी के देश अफ्रीका और यूरोप को भी जोड़ते हैं. माना जाता है कि अफ्रीकी आर्थिक गति 21वीं शताब्दी में तेजी से आगे बढ़ेगी. ग्रीन एनर्जी के वहां अनंत साधन हैं. भारत एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड का समर्थन करता है. यह दृष्टि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी है. इसलिए, आनेवाले समय में इस चतुर्भुज का प्रसार पूरे अफ्रीका में हो सकता है.इस क्षेत्र में अगर अवसर हैं, तो कई चुनौतियां भी हैं. सबसे अहम चुनौती चीन को लेकर है. चीन और इजरायल के बीच में सैनिक संबंध को लेकर अमेरिका ने भी विरोध प्रकट किया था. चीन ने पाकिस्तान में तैयार किये गये ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल ईरान के जरिये पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैलने के लिए भी किया है. दूसरी चुनौती अमेरिका के निहित स्वार्थ को लेकर भी बन सकती है. उसके इरादे भारत की सोच से अलग भी बन सकते हैं. लेकिन फिलहाल स्थिति भारत के अनुकूल है. चीन के विस्तार को पश्चिम एशिया में रोकने के साथ–साथ हिंद महासागर में भी अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है. इन कवायदों में यह समूह प्रभावकारी साबित होगा।

रक्षा निर्यात में वृद्धि

हमारा देश लंबे समय तक रक्षा साजो–सामान के सबसे बड़े आयातकों की सूची में रहा है, पर अब यह स्थिति जल्दी ही बदल जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया है कि बीते चार–पांच वर्षों की छोटी अवधि में रक्षा आयात में लगभग 21 प्रतिशत की कमी आयी है. घरेलू रक्षा उद्योग के तेज विस्तार से न केवल सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास हो रहा है, बल्कि रक्षा वस्तुओं का निर्यात भी लगातार बढ़ता जा रहा है.वित्त वर्ष 2021–22 में 13 हजार करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं अन्य देशों को बेची गयी थीं और इनमें से 70 फीसदी चीजों का उत्पादन निजी क्षेत्र के उद्योगों ने किया था. पहले की तुलना में सरकारी कंपनियों से खरीद का आंकड़ा बहुत बढ़ा है. सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आठ वर्षों में रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी होती रही है. पारंपरिक रूप से इसका बड़ा हिस्सा हथियारों और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर खर्च होता रहा है, पर अब घरेलू खरीद बढ़ने से हम विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ अपने उद्योगों को ठोस सहायता भी पहुंचा रहे हैं.इससे औद्योगिक विकास के साथ–साथ रोजगार व कारोबार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. भू–राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक खींचतान के कारण कई बार बाहर से हथियारों और रक्षा तकनीक की खरीद आसान नहीं होती. खरीद के बाद उन हथियारों की देख–रेख और उनके कल–पुर्जों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. युद्ध जैसी स्थितियों में या किसी मुद्दे पर तनातनी होने से ऐसे लेन–देन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. घरेलू रक्षा उद्योग के विकास से ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है. अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यरत है. इस अभियान का उद्देश्य है कि व्यापक घरेलू बाजार की मांग पूरी करने के साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में भी भारत की ठोस उपस्थिति बने. रक्षा क्षेत्र में इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के लिए 75 स्वदेशी तकनीकों और उत्पादों के विकास के कार्यक्रम की शुरुआत की है.वर्तमान में देश के भीतर 30 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य चल रहा है. चार युद्धपोत नौसेना के बेड़े में जल्दी ही शामिल होंगे. इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से अनिवार्य खरीद के लिए चिह्नित किया गया है. फ्रांस, रूस, इजरायल,फिलीपींस समेत अनेक देशों के साथ भारतीय कंपनियां कारोबारी समझौते कर रही हैं, जिनके तहत भारत में कई अहम चीजों और पुर्जों का निर्माण होगा तथा रक्षा तकनीक का विकास किया जायेगा. केंद्र सरकार ने 2020 में पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को 35 हजार करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. उम्मीद है कि 2025 तक भारतीय रक्षा उद्योग का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा.

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 25 जुलाई, 2022

इंडियन आइडल के ऑडिशंस पहुंचे लखनऊ

लखनऊ(यूएनएस)। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर जल्द शुरू होने जा रहे बहुप्रतीक्षित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के ऑडिशन आज लखनऊ में हुए। प्रसिद्ध श्री राम ग्लोबल स्कूल 2, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010 में ऑडिशन आयोजित किए गए। ऑडिशन राउंड सुबह 8 बजे से शुरू हुए, जिसमें आयोजन स्थल पर लगभग 1265 एंट्रीज देखी गईं। इंडियन आइडल एक क्रांतिकारी शो रहा है, जो नई प्रतिभाओं की पहचान करता है, उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है और उन्हें स्टार बनाता है। 2004 में प्रीमियर हुए इस शो ने देश को सलमान अली (सीजन 10 के विजेता), सनी हिंदुस्तानी (सीजन 11 के विजेता) और सीजन 12 के हाल के विजेता पवनदीप राजन जैसी कई अद्भुत आवाजों के साथ देश में हलचल मचा दी। अब यह शो सीजन 13 के साथ वापस आ गया है। लखनऊ में प्रतिभागियों की कुल संख्या–1265 से ज्यादा एंट्रीज इंडियन आइडल सीजन 13, जल्द आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।

लेखपाल भर्ती परीक्षा 31 जुलाई को

लखनऊ(यूएनएस)। यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई को किया जाएगा। इससे पहले इस परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई को होना था, लेकिन 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया गया था।इससे पहले भी परीक्षा 19 जून को होनी थी, जिसे 24 जुलाई के तक के लिए बढ़ा दिया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। परीक्षा में 10 दिनों से भी कम समय बचा है, ऐसे में यूपीएसएसएससी की ओर से जल्द ही एडमिट कार्ड जारी हो सकते है।लेखपाल भर्ती परीक्षा का एडमिट आधिकारिक वेबसाइट नचेब.हवअ.पद पर जारी किया जाएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 8085 पद भरे जाएंगे, जिसमें सामान्य के लिए 3271 पद, एससी के लिए 1690, एसटी के लिए 152, ओबीसी के लिए 2174 एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद आरक्षित हैं। परीक्षा क्लियर करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को चकबंदी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।

लखनऊ के बाबूजी की पुण्यतिथि पर दी गयी भावभीनी श्रद्धांजलि

लखनऊ(यूएनएस)। अपने संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त लखनऊ व आस–पास में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध सांसद लालजी टंडन को शहरवासियों ने उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर याद करके नमन किया। विकास पुरुष स्वर्गीय लाल जी टंडन की द्वितीय पुण्यतिथि कालीचरण पीजी कॉलेज चौक लखनऊ के सभागार में मनायी गयी और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के कुलपति एन0 बी9 सिंह थे। इस अवसर पर काली चरण पी जी कालेज के प्रबंधक इं0 वी0के0 मिश्रा, प्राचार्य चंद्र मोहन उपाध्याय, समस्त शिक्षक–शिक्षिकायें, कर्मचारी और छात्र–छात्राओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर लोगों ने विकास पुरूष लालजी टंडन को याद करते हुये श्रद्धासुमन अर्पित किये

नेता स्वार्थ छोड़ दें तो, समाज के अधिकारों के लिए मुंह खोलना सीख जायेंगे : लक्ष्य

लखनऊ(यूएनएस)। भारतीय समन्वय संगठन (लक्ष्य) की लखनऊ टीम ने लक्ष्य कमांडर अखिलेश गौतम के नेतृत्व में लक्ष्य 100 संपर्क कार्यालय अभियान के तहत ग्राम, सलेमपुर पतौरा, काकोरी जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में लक्ष्य कमांडर सुलोचना बौद्ध के निवास स्थान पर लक्ष्य संगठन के 28वें संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया तथा एक भीम चर्चा का भी आयोजन किया गया, बहुजन समाज के नेता स्वार्थ की चासनी में ऐसे चिपके हुए है कि उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता हैं अगर कभी उनके आका उनको स्वार्थ की चासनी नहीं देते है तब उनको समाज और उनके अधिकार याद आते है यह बात लक्ष्य कमांडरों ने अपने संबोधन में कही, उन्होंने कहा कि अगर नेता स्वार्थ छोड़ दें तो, समाज के अधिकारों के लिए मुंह खोलना सीख जायेंगे अर्थात् महापुरुषों के संघर्ष को समझ जायेंगे और गुलामी को लात मार देंगे। लेकिन ऐसा होगा नही इसलिए समाज के लोगो को अपने अधिकारों के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, इस कार्यक्रम में लक्ष्य कमांडर रेखा आर्या, संघमित्रा गौतम, विजय लक्ष्मी गौतम, राजकुमारी कौशल, अनीता गौतम, अनीता प्रसाद, बबिता सेन, देवकी बौद्ध, नीलम चौधरी, अखिलेश गौतम, अनिल कुमार, नंदकिशोर,ऋषभ, ए के तूफानी, सुनील, राहुल कुमार, गोविंद गौतम, शैलेश, कुमार, शैलेंद्र राजवांसी ने हिस्सा लिया।

क्या अब दूध–दही से जुड़े मुहावरों पर भी लगेगा जीएसटी, अखिलेश का तंज

लखनऊ(यूएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूध, दही और छाछ पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने को लेकर तंज करते हुए सरकार से प्रश्न किया कि क्या अब दूध–दही से जुड़े मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। यादव ने बृहस्पतिवार को 'जय श्री कृष्ण' के उद्बोधन से शुरू किए गए एक ट्वीट में तंज करते हुए कहा जन्माष्टमी से ठीक एक महीने पहले भाजपा सरकार ने दूध, दही, छाछ पर जीएसटी लगाकर जो चोट कृष्ण भक्तों को दी है, उससे आहत होकर हर एक कृष्ण भक्त पूछ रहा है कि क्या अब 'दूध का जला, छाछ भी', 'दूध का दूध 'दूधो नहाओ' जैसी लोकोक्ति–मुहावरों पर भी जीएसटी देना पड़ेगा? गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पैकिंग वाले दही, लस्सी, पनीर और छाछ जैसे दुग्ध उत्पादों पर 18 जुलाई से पांच फीसद जीएसटी लगा दिया है। इसके अलावा पैकिंग और लेबलयुक्त चावल, आटे और गेहूं पर भी जीएसटी लागू किया गया है, इससे इन रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं।

लोकायुक्त कार्यालय ने भेजा अमित मोहन प्रसाद को नोटिस

लखनऊ(यूएनएस)। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर विवाद और कई आरोपों से घिरे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अमित मोहन प्रसाद को लोकायुक्त संगठन की तरफ से एक नोटिस भेज कर 28 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। लखनऊ निवासी राजेश खन्ना की तरफ से अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत की गई है।उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय के सचिव अनिल कुमार सिंह ने अमित मोहन प्रसाद को पत्र भेजकर राजेश खन्ना के परिवाद पर उनका जवाब मांगा है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की खरीद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त के यहां शिकायत हुई थी, जिसको लेकर राजेश खन्ना की शिकायत पर 28 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने व पेश होकर शिकायत के बारे में जानकारी मांगी गई है।कोरोना काल के दौरान घटिया पीपीई किट सप्लाई के साथ मेडिकल उपकरण द्वारा दवा खरीद के मामले में राजेश खन्ना द्वारा लोकायुक्त से शिकायत की थी।

कार्मिक विभाग ने जारी किया कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगों पर कार्यवृत्त

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुई थी विगत दिनों वार्ता

लखनऊ(यूएनएस)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि शासन के कार्मिक विभाग ने संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हुई वार्ता का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। जारी किए गए कार्यवृत्त में संयुक्त परिषद की प्रमुख 16 मांगों पर निर्णय से संयुक्त परिषद को अवगत कराया गया है। कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों पर सकारात्मक निर्णय हुए हैं एवं मांगों को पूरा करने का रोड मैप भी कार्यवृत्त में है। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि रिक्त पदों को भरे जाने के लिए 22 फरवरी 2022 एवं 20 अप्रैल 2022 को सभी विभागों को सख्त निर्देश भेजे जा चुके हैं। पदों को भरने के लिए अनुस्मारक भेजा जा रहा है। सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, सहित सभी संवर्गों की वेतन विसंगतियों, समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर मुख्य सचिव समिति से निर्णय कराए जाने के लिए वित्त विभाग को निर्देश भेजे जाने का निर्णय हुआ है। नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करने के लिए भी वित्त विभाग कार्यवाही करेगा। नगरीय परिवहन सेवाओं में सभी महानगरों में कार्यरत संविदा चालक परिचालकों को एक समान मानदेय देने एवं एक विभाग एक एम डी की तैनाती पर नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर नियुक्ति विभाग कार्यवाही करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संरक्षण एवं सेवा में निरंतरता के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कार्मिक विभाग से पुनः निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रोत्साहन राशि पर कार्यरत आशा बहुओं एवं अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम 15000 का मानदेय देने के प्रस्ताव पर चिकित्सा विभाग विचार कर रहा है। आशा कार्यकत्रियों को बढ़ा हुआ मानदेय एवं कोविड भत्ते के भुगतान के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत एल टी ग्रेड शिक्षकों को नियमित किए जाने के लिए समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भेजे गए हैं। कार्य देशक के 33: पदों को आउटसोर्सिंग से अलग करने के लिए तथा कार्य देशक के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा विभाग को कार्यवाही के निर्देश भेजे गए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किए जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में की गई प्रेक्षा पर विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के विषय में वित्त विभाग को लिखा गया है। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि बैठक, अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। बैठक में वित्त, कार्मिक,समाज कल्याण, राजस्व, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला बाल विकास पुष्टाहार, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जबकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला, चकबंदी अधिकारी संघ के अध्यक्ष पुनीत शर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद नगरीय परिवहन इकाई शाखा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह,आईटीआई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह एवं आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन की अध्यक्ष कुसुम लता उपस्थित थीं।

मुख्य सचिव से ब्रह्म कॉर्पोरेट समूह और आईसीएसटी संयुक्त उद्यम के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की

लखनऊ(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से बीआईडीजेवी (एक ब्रह्म कॉर्पोरेट समूह और आईसीएसटी संयुक्त उद्यम) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रह्म इंडियन डेवलपमेंट ज्वाइंट वेंचर (बीआईडीजेवी) की ओर से भावुक त्रिपाठी (अध्यक्ष), राजा सीवन (अध्यक्ष) और सौरव सचिन (सीईओ) ने किया।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने तथा उद्योगों की स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में पूंजी निवेश एवं उद्योग स्थापना की असीम संभावनायें हैं। 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओ0डी0ओ0पी0) के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। राज्य सरकार आई0टी0 एवं मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ–साथ राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रदेश सर्वाधिक 05 एक्सप्रेस–वे और 09 एयरपोर्ट वाला राज्य है। शीघ्र ही 05 और एयरपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 05 इन्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी बनने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को 250 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक सर्वोत्तम नवाचारों के साथ आगे ले जाने पर सार्थक विचार–विमर्श किया गया। ब्रह्म कॉरपोरेट ग्रुप के संस्थापक भावुक त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश को हर संभव तकनीकी और विकासात्मक समर्थन देने तथा व्यवहार्य, परिवर्तनकारी परियोजनाओं में 8000 करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में भागीदारी व सहयोग के लिये अमेरिकी राज्यों–जॉर्जिया, इंडियाना एवं व्योमिंग और स्पेन व मैक्सिको देशों से उच्चतम स्तर पर नेटवर्किंग के अवसरों को भी उपलब्ध करायेंगे। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि किसानों की आय को संभावित रूप से दोगुना करने के मामले में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, टी0बी0 मुक्त भारत बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर ध्यान देने के लिए भूमि प्रशासन विभागों के लिये पारदर्शी, सुरक्षित और आसान तकनीक, साइबर सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न विभागों में डिजिटल एकीकरण तथा कई अन्य प्रतिमान बदलने वाली परियोजनाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के साथ साझा करना चाहती है। आईसीएसटी ने ई–पशुहाट, किसान मित्र, स्मार्ट सिटी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार किये हैं। यह संयुक्त उद्यम इन्वेस्ट यूपी मिशन में सहयोग करने के साथ राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अपना योगदान देने का प्रयास करेगा। इस अवसर पर सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बीआईडीजेवी के अन्य पदाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

ईडी ऑफिस पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन

लखनऊ(यूएनएस)। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी लखनऊ दफ्तर में नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है। इसके खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। सोनिया गांधी से पूछताछ का समन जारी हुआ था। सोनिया कोविड संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। जून में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा। जिसे ईडी ने मंजूर किया था। कांग्रेस पदाधिकारियों का पूरे मामले पर कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत फायदा उठाते हुए पार्टी नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरीके की सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे लोकतंत्र खतरे में है। इससे पहले ईडी नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। पांच दिनों तक ईडी के अधिकारी राहुल गांधी से 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पूछताछ करते थे। उस दौरान भी कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया था। इस बार भी कांग्रेस नेताओं ने देशभर में विरोध–प्रदर्शन कर रही है। मामला 1 नवंबर 2012 को तब शुरू हुआ, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दायर किया। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया था। मोतीलाल वोरा व आस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। अब यह मामला वर्तमान में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में चल रहा है। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90.25 करोड़ रुपए की वसूली का अधिकार प्राप्त किया गया जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।

सीएमएस छात्रों ने 'पानी बचाओ' मार्च निकाला

लखनऊ(यूएनएस)। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजेन्द्र नगर (द्वितीय कैम्पस) के छात्रों ने आज एक विशाल मार्च निकालकर बड़े ही जोरदार तरीके से जनमानस को जल–संरक्षण हेतु प्रेरित किया एवं जल के महत्व को विस्तार से बताया। छात्रों के इस मार्च का नेतृत्व प्रधानाचार्या शमीम सिंह ने किया। जनमानस ने सी.एम.एस. छात्रों की इस मुहिम की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए छात्रों का खूब उत्साहवर्धन किया। इस विशाल मार्च में सी.एम.एस. छात्रों ने नारे लगाते हुए एवं हाथों में बैनर–पोस्टर आदि लेकर राजेन्द्र नगर क्षेत्र में घूम–घूमकर जनमानस को जल संरक्षण के प्रति सचेत किया और पेयजल की सीमित उपलब्धता, जल प्रदूषण, जल की बर्बादी आदि विभिन्न मुद्दों पर जागरूक किया। सी.एम.एस. छात्रों ने 'सेव वाटर', 'प्रिजर्व वाटर, प्रिजर्व लाइफ', 'पानी बहुमूल्य नहीं अमूल्य है', 'पेयजल असीमित नहीं, सीमित है' आदि नारे लगाते हुए जल संरक्षण का अलख जगाया और स्वयं भी जल संरक्षण का संकल्प लिया। इससे पहले, जल संरक्षण मार्च का शुभारम्भ करते हुए सी.एम.एस. राजेन्द्र नगर (द्वितीय कैम्पस) की प्रधानाचार्या शमीम सिंह ने कहा कि दैनिक जीवन में जल के महत्व से हम सभी परिचित हैं, परन्तु फिर भी जल की बर्बादी व जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं है। जल संसाान के महत्व को अगर नहीं समझा गया तो हम अपने वर्तमान के साथ ही भविष्य को भी अंधकार में डुबो रहे हैं। इसलिए बच्चों को बाल्यावस्था से ही जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। विद्यालय के संस्थापक डा. जगदीश गाँधी ने सी.एम.एस. राजेन्द्र नगर कैम्पस के छात्रों, शिक्षकों व प्रधानाचार्या को इस सामाजिक कार्य हेतु हार्दिक बधाई दी है। सी.एम.एस. के मुख्य जन–सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. छात्र जन–जागरूकता के कार्यो में सदैव ही अग्रणी रहे हैं और यह जल संरक्षण मार्च भी इसी की एक कड़ी है। आज आवश्यकता है कि समाज का प्रत्येक नागरिक जल, ऊर्जा एवं पर्यावरण के बारे में जागरूक व संजीदा हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सी.एम.एस. छात्रों का यह मार्च किशोरों व युवाओं को पर्यावरण व जल सरंक्षण हेतु प्रेरित करेगा।

मंत्रियों और हाकिमों की खींचतान कामकाज में आड़े

मंत्री दिनेश खटीक की चिट्ठी सामंजस्य की कमी का प्रमाण

लखनऊ(यूएनएस)। सौ दिनी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या पेश करने का योगी का फरमान आया मंत्रालयों से लेकर आला हाकिमों के बीच चल रही खींचतान और सामंजस्य की खामी उभर कर आ गई। तबादला नीति का अनुपालन ठीक से नही हुआ तो बवाल मच गया। तीन तीन साल पहले मर चुके अफसरों का तबादला आदेश जारी हो जाने के बाद चिंता तो स्वाभाविक है। मंत्री कहते अफसर नही सुनते। अफसर खुलकर भले ही नही बोल रहे लेकिन उनके विचार कुछ मन्त्रियों के प्रति जुदा नही हैं। जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक की गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी ने खींचतान को आमजन के बीच उजागर कर दिया है। आखिर उन्हें इस्तीफे की पेशकश करने की नौबत क्यों आयी,यह सवाल आमजन के जेहन में कौंध रहा है। सीएम हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति से तनिक भी इधर उधर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। सीएम की सख्ती और ट्रांसपरेंसी ही उनकी असली पहचान है। प्रदेश सरकार में मंत्रियों और नौकरशाही के बीच खींचतान सतह पर आ गई।

कई विभागों में मंत्रियों और आला अफसरानों में तालमेल की कमी आड़ेआ रही है। विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।कई मंत्रियों ने तो अपने महकमे के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को बदलने की सिफारिश भी कर दी है, लेकिन अभी तक बदला कोई नहीं है।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह की भी कहा जा रहा है कि प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव व सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से नहीं पट रही है। वे दोनों को बदलने का आग्रह कर चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की खींचतान जगजाहिर है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा का भी यही हाल है। उनकी भी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज से ठीक बैठ नहीं रही है। एम देवराज की कार्यशैली को लेकर स्वयं नौकरशाह रहे शर्मा लखनऊ से दिल्ली तक शिकायतें कर चुके हैं। वही प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण से तालमेल नहीं है। जितिन प्रसाद ने तबादलों में भूषण की भूमिका पर सवाल उठाए और कामकाज पर भी नाराजगी जता चुके हैं। आबकारी राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल के विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी से नहीं बन रही है। नितिन ने भी सरकार और संगठन में अपनी पीड़ा का इजहार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हो या फिर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह हो अथवा बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, ये भी विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं। जब हुकूमत के जिम्मेदार ही मिलकर काम नहीं करेंगे तो कामकाज प्रभावित होने से कौन बचा सकता है। अब सबकी निगाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर लगी हैं।

विभागों में भ्रष्टाचार से जनता में खत्म हुआ सरकार का इकबाल : रालोद

सम्बंधित मंत्रियों को बर्खास्त कर कराये उच्च स्तरीय जांच

लखनऊ(यूएनएस)। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रभारी सदस्यता अभियान सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री के ओएसडी की बर्खास्तगी और जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ साथ दलित विरोधी होने का समुचित प्रमाण है। श्री खटीक ने मंत्री पद से इस्तीफा के साथ साथ विभाग में स्थानान्तरण सत्र में किये गये भ्रष्टाचार और नमामि गंगे जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। स्वास्थ्य विभाग में किये गये स्थानान्तरण सर्वप्रथम ही उजागर हो चुके हैं और विभागीय भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ चुका है।श्री त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इनका संज्ञान नाम मात्र लेने से काम नहीं चलेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी विभागों के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करके उच्चस्तीय जांच कराई जाए और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि इन घटनाओं से प्रदेश की जनता में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि खटीक का इस्तीफा सरकार का दलित विरोधी चेहरा जनता के सामने ला चुका है जिससे इस वर्ग के लोग आक्रोशित हैं जो सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करने वाला सरकार का प्रारूप लगता है जल शक्ति विभाग में भी राज्यमंत्री के अनुसार चारो तरफ घोटाला ही घोटाला है।रालोद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार घोटालों में आकण्ठ डूबी हुयी है। इसका प्रमाण विभागीय कारगुजारियों के साथ साथ मंत्रियों के क्रियाकलाप से भी स्पष्ट होता है। सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पूर्णतः खोखला सिद्ध हो चुका है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि सरकार ने स्थानान्तरण सत्र नहीं बल्कि तबादला उद्योग चलाया है जो सरकार पर एक बदनुमा दाग ही कहा जायेगा। राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों और उनके चहेते कर्मचारियों को सामाजिक अथवा सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जाय ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ आमजनमानस तक आसानी से पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने लालजी टण्डन पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

लखनऊ(यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री स्व0 लालजी टण्डन की पुण्यतिथि पर आज यहां हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लालजी टण्डन लखनऊ की एक पहचान थे। लखनऊ के विकास और लखनऊ के माध्यम से प्रदेश को एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। वह सभी राजनीतिक दलों के प्रिय थे। अपनी सहज, सरल एवं संवेदनशील दृष्टि के कारण उन्होंने सभी को अपने साथ जोड़ा था। टण्डन जी ने प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। उन्होंने प्रदेश शासन के कई विभागों का नेतृत्व किया। टण्डन जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के अनन्य सहयोगी थे। अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने प्रयास किये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री लालजी टण्डन की स्मृतियां हर उम्र के लोगों के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी स्मृतियों को 'अनकहा लखनऊ' पुस्तक के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया था। टण्डन जी ने पार्षद से लेकर राज्यपाल के पद तक 05 दशक से भी अधिक समय की अपनी यात्रा को कुशलतापूर्वक पूर्ण किया था। उनका योगदान अविस्मरणीय है।

नाराजगी अफसरों से है, मुख्यमंत्री और किसी मंत्री से नही : खटीक

लखनऊ(यूएनएस)। दलित होने के कारण उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने आज मेरठ में कहा कि उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार के किसी भी मंत्री से नहीं बल्कि मनमानी कर सरकार को बदनाम कर रहे कुछ अफसरों से नाराजगी है। खटीक ने आज संवाददाता सम्मेलन में दलित होने की वजह से उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश और इस सिलसिले में सार्वजिक हुए एक पत्र के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरी मुख्यमंत्री या सरकार के अन्य किसी भी मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। वह कुछ अफसरों से नाराज हैं, जो मनमानी करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 'कतई बर्दाश्त न करने' की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान चाहिए मगर कुछ अफसर सम्मान तो अलग बात है मांगने पर सूचना भी नहीं देते हैं। खटीक ने दलित होने के चलते अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मंत्री ने विभाग में भ्रष्टाचार होने का आरोप भी लगाया था।खटीक ने एक ओर अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा तो दूसरी ओर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर उन्हें भी एक प्रति दी थी।पत्र में दिनेश खटीक ने दलित होने के कारण अधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने, तबादलों और नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 25 जुलाई, 2022

शिक्षक दंपति के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

जौनपुर। सीसीटीवी कैमरे घर की रखवाली कर रहे हैं और पुलिस ड्रोन के जरिए अपराध पर नियंत्रण कर रही है जबकि वही बेखौफ अपराधियों की टोली हमजोली बनकर अपराध का मंत्रण कर रहे हैं। शहर के लाइन बाजार थाना अंतर्गत मुरादगंज स्थित टीचर कॉलोनी में बुधवार को दोपहर चोरों ने पुलिस की हिकमत अमली और मुखबिर सूत्र को नाकाम कर शिक्षक दंपति के घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात समेत करीब ढाई लाख से अधिक का माल पार कर दिया। चोरों ने तकरीबन 45 मिनट में मकान के सारे कमरों को खंगाल डाला और कीमती सामान समेट कर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई चोरी की यह वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई । सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मुरादगंज में स्थित टीचर कॉलोनी निवासी हरिकेश मौर्य और उनकी पत्नी नंदिनी मौर्या दोनों बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक हैं । बुधवार को दोनों पति पत्नी विद्यालय गए थे । बच्चे भी स्कूल गए थे। घर में ताला बंद था। दोपहर में करीब दो बजे नंदनी स्कूल से घर पहुंची तो देखा मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था । उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुट गए । लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अलग–अलग कमरों में अलमारियां टूटी हुई थी और उसमें रखा 50 हजार नकदी, दो लाख से अधिक के जेवरात गायब थे । चोरों की बीन छान के पश्चात सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी छानबीन किया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला मुख्य गेट को फादकर बाउंड्री के अंदर कूदने से लेकर ताला तोड़ने और घर के अंदर से सारे नगदी और जेवरात समेट कर बाहर निकलने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे छानबीन में जुटी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष लाइनबाजार का कहना है कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस छानबीन में जुटी है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा।

अविश्वास प्रस्ताव से ब्लाक प्रमुख खेमे में खलबली

जौनपुर। मड़ियाहूं के रामपुर में ब्लाक प्रमुख पद पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जंग शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वर्तमान ब्लाक प्रमुख खेमे में खलबली है। वर्तमान ब्लाक प्रमुख और चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे प्रत्याशी ने बीडीसी इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को विपक्षी खेमा डीएम के सामने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। दोनों पक्ष अपने पास अधिक बीडीसी होने का दावा कर रहे हैं। वर्तमान में रामपुर ब्लाक में नीलम सिंह ब्लाक प्रमुख हैं। रामपुर ब्लाक में कुल 100 बीडीसी सदस्य हैं। सुरेरी की एक बीडीसी की मौत हो जाने के बाद वर्तमान समय में 99 बीडीसी रह गए हैं। करीब एस साल पहले हुए ब्लाक प्रमुख के चुनाव में नीलम सिंह पत्नी राजेश सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी राहुल सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। इसमें राहुल सिंह को 44 मत मिले थे, जबकि विजयी होने वाली नीलम सिंह को 55 वोट मिले थे। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव का समय नजदीक आया राहुल सिंह के खेमे की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच जंग छेड़ दी गई। अविश्वास प्रस्ताव का पता चलते ही वर्तमान ब्लाक प्रमुख के खेमे में हलचल तेज हो गई है। राहुल सिंह और नीलम सिंह खेमे के लोग अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दबी जुबान तैयारी की बात भी बता रहे हैं। राहुल सिंह की माना जाय तो 65 से लेकर 70 बीडीसी सदस्यों को अपने साथ कर लिया हैं। सूत्र बताते है कि सोमवार अथवा मंगलवार को जिलाधिकारी के सामने शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। इस बारे में फोन पर वार्ता के दौरान राहुल सिंह से चर्चा हुई तो उन्होंने दबी जुबान कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी जरूर की जा रही है। हमारे साथ काफी संख्या में बीडीसी सदस्य हैं। दूसरी तरफ ब्लाक प्रमुख नीलम सिंह के प्रतिनिधि विपिन सिंह ने बताया कि कुछ बीडीसी को उठाया गया है। इसकी सूचना हमने रामपुर, नेवढ़िया और सुरेरी थानों के थानाध्यक्ष को मौखिक रूप से दी है। मैं पूरी तरह तैयार हूं मेरे साथ क्षेत्र के सम्मानित बीडीसी आज भी है और कल भी रहेंगे। मैं चट्टान की मजबूती के साथ पूरी तरह मजबूत हूं।

भारी बारिश से किसान गदगद

जौनपुर। बुधवार को दोपहर दोपहर बाद से झमाझम बारिश हुई। लगातार धीमा ओर तेज वारिश गुरूवार को दोपहर में थमी। धान की फसल में पानी चलवाने की तैयारी में जुटे किसान बारिश से गदगद दिखे। हालांकि बारिश ने शहर और कस्बों की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। जगह–जगह पानी लगने से लोगों को आने–जाने में दिक्कत हुई। सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से वह खतरनाक हो गए। पिछले दिनों से धूप और उमस से परेशान लोगों को बारिश ने काफी राहत दी। किसानों का कहना था कि धान की रोपाई के लिए पानी की जरूरत थी। लोग अन्य साधनों से खेत में पानी कर धान रोप रहे थें। बारिश ने किसानों की बहुत बचत की है। धान के साथ ही अन्य फसलों को बारिश से बहुत लाभ हुआ है। 18 घण्टे धीमा और तेज बारिश से ही घरों में कई स्थानों पानी घुस गया। बारिश ने ही कुछ मोहल्लों में नारकीय स्थिति पैदाकर दी। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया कि नालों और नालियों की सफाई सिर्फ कागज में होने के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी पहुंच रहा है।

रेल ट्रैक पर बाइक छोड़, गिरफ्तार

जौनपुरं शाहगंज आजाद नहर स्थित रेल ट्रैक पर एक सप्ताह पूर्व बाइक छोड़कर भागे आरोपित मोहम्मद शाहिद बलुआघाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक बाइक लेकर ट्रैक पार कर रहा था। उसी समय टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस करीब आती दिखने पर वह ट्रैक पर बाइक छोड़कर भाग गया था। ट्रेन की चपेट में आने से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे के कारण ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। आरपीएफ ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर अज्ञात सवार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था।

स्कूल में सफाई न होने पर डीएम ने फटकारा

जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा प्राथमिक विद्यालय पांडेपुर एवं इंग्लिश मीडियम विद्यालय हसनपुर सिकरारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि विद्यालय में कुल 71 बच्चे पंजीकृत है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बच्चों की संख्या और बढ़ाये जाने के लिए प्रधानाध्यापक संतोष सिंह को निर्देश दिया। विद्यालय में साफ–सफाई एवं परिसर में सामान बिखरे हुए पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल को निर्देशित किया कि सभी विद्यालयों में अभियान चलाकर साफ–सफाई के कार्य कराए जाएं। स्कूल परिसर में किनारे–किनारे इंटरलॉकिंग लगाने और बीच में छोटा सा खेल का मैदान बनाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। इंग्लिश मीडियम विद्यालय हसनपुर के निरीक्षण के दौरान अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों से एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी हो और विषय उन्हें रोचक लगे। विद्यालय में रखे फायर यंत्र को अपडेट करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। किचेन की फर्श को ऊपर किये जाने का निर्देश खंड विकास अधिकारी सिकरारा को दिया। निरीक्षण के दौरान गांव की सविता गौतम के द्वारा बताया की बीए की पढ़ाई करने के उपरांत घर पर ही सिलाई कढ़ाई करती हूँ, जिस पर उन्हें समूहों से जोड़ने एवं कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिये गए। सहायक अध्यापक राज कुँवर सिंह, मधुलिका यादव, कुसुम पांडये, प्रधानाध्यापक रवि प्रकाश मिश्रा, संगीता सिंह, सविता यादव, शिक्षामित्र चंदन सहित अन्य उपस्थित रहे।

बारिश से नाले का गन्दा पानी घरों में घुसा

जौनपुर। एक ही बारिश ने मियांपुर के निवासियों का जीना दुश्वार कर दिया, क्योंकि मोहल्ले के नाले का पानी आगे न बढ़ने से अगल–बगल के घरों में घुसना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी से शिकायत करते हुये उक्त मोहल्लेवासियों ने कहा कि नाले से पानी पास नहीं हो रहा है जिसका कारण छोटा पाइप लगना है। यह निर्माण कार्य लगभग 3 माह पूर्व किया गया है। बीते बुधवार को हुई बारिश के चलते नाले का पानी अगल–बगल स्थित घरों में घुस गया। लोगों के अनुसार इसके पहले बड़ा नाला था जिसके चलते इस समय की समस्या कभी नहीं होती थी। नगर पालिका सहित अन्य सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नाले के पाइप को छोटा कर दिया गया है जिसके चलते उपरोक्त समस्या उत्पन्न हो गयी है। गुरूवार को जिलाधिकारी से मिलकर समस्या के समाधान की मांग किया जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया। शिकायत करने वालों में आरती देवी, देवी प्रसाद गुप्ता, मनोज विश्वकर्मा, बृजेश गुप्ता, विशाल गुप्ता, अशोक गुप्ता, रेखा गुप्ता, साहब लाल एडवोकेट, शशिंकर एडवोकेट, सूरज गुप्ता, बबीता गुप्ता, आशा गुप्ता, विरजू गुप्ता आदि प्रमुख रहे।

श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना'

जौनपुर। विधायक रमेश सिंह ने गुरुवार को भोर में शाहगंज रेलवे स्टेशन से अमरनाथ यात्रा पर निकले 131 श्रद्धालुओं के जत्थे को फल–फूल तथा वस्त्र भेंट करके रवाना किया। श्रद्धालुओं का जत्था नगर पालिका शाहगंज की अध्यक्ष गीता जायसवाल के पति प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में आठ दिवसीय यात्रा पर निकला है।भोर में चार बजे सियालदह–जम्मूतवी ट्रेन से रवाना हुआ यात्रियों का दल शुक्रवार को जम्मू पहुंचेगा। वहां से बस द्वारा श्रीनगर और फिर पैदल पहलगाम होते हुए बाबा बर्फानी का दर्शन करेगा। इस दौरान विधायक श्री सिंह ने कहा कि भगवान शंकर आदि देव हैं। उनकी प्रसन्नता व कृपा से ही मानव जीवन मे खुशहाली व संपन्नता आती है। भाग्यशाली लोगों को ही उनके दर्शन का लाभ मिलता है। उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक कि ऐसी धार्मिक यात्राएं राष्ट्र की अखंडता को भी बढ़ावा देती हैं। हम सभी को अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर इन्हीं यात्राओं के माध्यम से अपने इस विशाल देश को जानने–समझने का प्रयास भी करना चाहिए। रूपेश जायसवाल, संजय चौबे, राजेश सिंह, संदीप साहू, अर्पित जायसवाल, राज कुमार अग्रहरि, अजय मोदनवाल , ओम चौरसिया सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

भ्रष्टाचार के आरोप में सीएलटीसी बर्खास्त

जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी में षडयंत्र करके वित्तीय अनियमिता एवं भ्रष्टाचार करने वाले डूडा के सीएलटीसी यशवीर सिंह को अपर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ ने बर्खास्त कर दिया। परियोजना अधिकारी डूडा अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी यशवीर सिंह को सन् 2018 में सूडा लखनऊ द्वारा उक्त पद पर यहां आबद्ध किया गया था। श्री सिंह कन्सलटेन्ट एमआईएस के साथ आपराधिक षडयंत्र करके प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के 07 लाभार्थियों को दुबारा प्रथम किस्त की धनराशि पचास–पचास हजार तथा 05 लाभार्थियों को दुबारा द्वितीय किस्त की धनराशि डेढ़–डेढ़ लाख एवं 12 ऐसे व्यक्ति जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के डीपीआर में शामिल ही नही है को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि तथा 03 लाभार्थियों के प्रथम किस्त की धनराशि दूसरे व्यक्ति के खाते में अवमुक्त कर वित्तीय अनियमिता एवं भ्रष्टाचार किया गया। इस मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा सीएलटीसीएवं एमआईएस को नौकरी से निकालने एवं नोटिस देकर धनराशि की वसूली करवाने तथा जिलाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने का आदेश दिया गया। मुख्य राजस्व अधिकारी के निर्देश के क्रम में सीएलटीसी को नोटिस दी गई है, किन्तु श्री सिंह वसूली कार्य के प्रति उदासीन रहे, जिसके कारण जिलाधिकारी के आदेश पर सीएलटीसी एवं तत्कालीन एम0आई0एस0 आमिर खान के विरूद्ध थाना लाइन बाजार में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई और कार्यवाही हेतु निदेशक सूडा लखनऊ को सूचित किया गया जिस पर सूडा मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से सीएलटीसी यशवीर सिंह की सेवा समाप्त कर नौकरी से बाहर कर दिया है।

बारिश के बाद जलजमाव का दंश झेलता कजगांव बाजार

जौनपुर। स्वच्छता अभियान को शासन द्वारा नवसृजित नगर पंचायत कजगांव बाजार मुंह चिढ़ा रहा है। बरसात होते ही सड़कों पर पानी डूब जाता है जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है कारण हैं कि उक्त बाजार की नालियां जगह–जगह टूट जाने से पूरे बाजार का गन्दा पानी से जल– जमाव के कारण नरकीय बना हुआ है सादात मसौड़ा कजगांव बाजार में नालियां जगह–जगह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लोगों के घरों व दुकानों से निकलने वाले गन्दे पानी से सिरकोनी– रसैना मार्ग पर कजगांव नई बाजार चौराहा,पुरानी बाजार व पानी टंकी चौराहा पानी से डूबा हुआ है जल निकासी के अभाव के कारण उक्त चौराहा झील में तब्दील हो गया है जिससे राहगीरों को आवागमन का भारी परेशानी उठानी पड़ रही है चौराहे के आस–पास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है उक्त भीषण जल जमाव के कारण दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है यहां तक कि लोगों का कहना यह है कि नगर पंचायत के द्वारा सड़क के अगल–बगल बनी नालियां भी ठीक ढंग से साफ नहीं कराई जाती अगर नालियां ठीक ढंग से साफ कराई जाती तो शायद इस प्रकार से सड़क पर पानी नहीं डूबता बताया जाता है कि शासन–प्रशासन के साथ–साथ सांसद,विधायक,ग्राम प्रधान द्वारा उक्त जल–जमाव के निवारण के लिए कार्य नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों में रोष है।

महंगाई के खिलाफ आन्दोलन करेगी आम आदमी पार्टी

जौनपुर। आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में एक बैठक जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना के अध्यक्षता में हुआ । बैठक में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनीता मिश्रा भी उपस्थित रही। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूनम सिंह को महिला प्रकोष्ठ का जिला महासचिव बनाया गया और साधना त्रिपाठी को महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और चंद्र का मिश्रा को जिला सचिव मनोनीत किया गया इसी जिला अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ संगठन निर्माण में जुटी हुई है और नगर पालिका का चुनाव एवं नगर पंचायत का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है इसलिए वार्ड स्तर तक संगठन का निर्माण किया जा रहा है सभी नए पदाधिकारियों को बहुत–बहुत बधाई इसी क्रम में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनिता मिश्रा ने कहा कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और महिलाएं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है परिवार चलाना मुश्किल हो गया है गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं इस महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी इस कार्यक्रम में शामिल साथी विद्याधर मिश्रा, अमरनाथ यादव ,जयप्रकाश चौहान, डॉ दिवाकर मौर्य ,मनीष सिंह ,इस्लाम भाई, विनोद आदि लोग शामिल हैं।

महिला झुलसी, मन्दिर का गुम्बद ढहा

जौनपुर। मीरगंज थाना क्षेत्र के दो अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली की चपेट मे आने से एक महिला झुलस गईं, जबकि निर्माणाधीन मंदिर का गुम्बद भी ढह गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चौथार गांव निवासी 25 वर्षीय अंजू देवी पत्नी धनंजय विश्वकर्मा खाना खाकर रात में सोई हुई थी। घर के एक सिरे पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। जिससे वह झुलस गई। घर का एक भाग भी क्षति ग्रस्त होने के साथ ही घर मे लगे विद्युत उपकरण टीवी, पंखा आदि जल गए। परिजन महिला का उपचार एक निजी चिकित्सक के यहां करा रहे हैं। वहीं रामगढ़ गोगावल गांव में बुधवार की देर शाम शुरू हुई बारिश के दौरान रात में एक निर्माणाधीन हनुमान मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुम्बद व छत का हिस्सा टूट गया। संयोग ही रहा कि मंदिर के आसपास के सदस्य बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बताते चले कि रामगढ़ निवासी पवन दुबे हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे है। बीती रात तेज बारिश के दौरान अचानक तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली उनके मंदिर की गुम्बद पर आ गिरी। जिससे मंदिर का गुम्बद व छत क्षतिग्रस्त हो गया।

करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरहूपुर गांव मे अपनी बुआ के घर आये युवक की करंट की चपेट में आने से गुरुवार को मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुजानगंज थाना क्षेत्र के शेषनगर अहिलादपुर निवासी 30 वर्षीय सुभाष यादव पुत्र स्वर्गीय इंद्रमणि यादव महराजगंज थाना क्षेत्र के बरहूपुर निवासी अपनी बुआ अंजनी यादव के घर आया था। इसी दौरान टेबल पंखा में करंट प्रवाहित होने लगा, जिसकी चपेट में सुभाष यादव आ गए। परिजन आनन–फानन में अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मृत युवक के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गये। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।

जहरीले जंतु के डसने से मासूम की मौत

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के सेंधीपुर गांव में बुधवार की देर शाम को विनोद यादव की 6 वर्षीया पुत्री रूपा यादव को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। परिजनों के द्वारा काफी भाग दौड़ के बाद भी मासूम की मौत हो गयी। बताते है कि रूपा अपने उम्र के बच्चों के साथ घर के पास एक बास की कोठ के पास खेल रही थी। उसे वहीं पर किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। घर आकर वह अचेत हो गयी। परिजनो ने देखा उसके पैर में किसी जानवर के काटने का निशान है। उसे कई चिकित्सक को दिखाया गया। परन्तु वह नहीं बच सकी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

शौचालय के लिए करें आन लाइन आवेदन

जौनपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया है कि मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों द्वारा शौचालय की मांग हेतु भारत सरकार की वेबसाइट पर डिजीटाईज्ड आनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराने हेतु आनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा सकते है। आनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया अपनायी जायेगी। आनलाइन आवेदन हेतु सम्बन्धित सिटीजन द्वारा एसबीएम (जी) पोर्टल या वेब लिंक पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन उनके मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, कामन सर्विस सेन्टर इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है। सम्बन्धित सिटीजन आवेदक द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के उपरान्त लागिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा। उपरोक्त लागिन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सम्बन्धित सिटीजन आवेदक द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन धनराशि की सहायता हेतु आवेदन जमा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्यजन जिनका व्यक्तिगत शौचालय विभागीय योजनान्तर्गत प्रोत्साहन की धनराशि से निर्मित कराये गये है तथा निर्मित कराये गये शौचालयों में अवश्यकतानुसार रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जाना है, हेतु आनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

मोटर दुर्घटना का करायें निस्तारण

जौनपुर । पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी है, जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी याचिकाओं का सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना है। लोक अदालत में अधिकतम वादों का निस्तारण किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा सुलह समझौते के वादों को चिन्हित करने के लिए प्री–ट्रायल बैठके 22 जुलाई, 26 जुलाई, 05 अगस्त, 08 अगस्त एवं 10 अगस्त को आयोजित की जानी है। प्री–ट्रायल बैठकों में सुलह–समझौता हेतु चिन्हित किये गये वादों का निस्तारण 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा।

कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लखनऊ में हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में जनपद की स्वास्थ्य इकाई गुरुवार को यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। लोगों ने एक साथ मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय सभागार में योजना के बारे में जानकारी ली। बताया गया।

सम्पदाकीय कार्यालय

वैशवारा पत्र के प्रधान संपादक रमाकान्त पाण्डेय गोपालपुरी के लिए प्रकाश एवं मुद्रक सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा उमरपुर हरिवन्धनपुर नईगंज जौनपुर से प्रकाशित किया। स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अरूणा प्रेस मेंहनगर आजमगढ़ से प्रकाशित किया।
सम्पादक : सुनील कुमार श्रीवास्तव
मो. 9455322393
सह सम्पादक डा. आदित्य सिंह
मो. 9415893741
जिला संवाददाता : हरिशचन्द्र यादव
मो. 8858583480
कानूनी सलाहकार (एडवोकेट) : सन्तोष कुमार श्रीवास्तव

Email:- vaashvara.123hr@gmail.com
Website:- vaashvara.com

समाचार पत्र में छपी सामग्री के लिए लेख व संवाददाता स्वयं जिम्मेदार होगा पी.आर.वी. के तहत